हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन
और
आजीविका सुधार परियोजना (JICA वित्तपोषित)

संवाद पत्र

अंक 18: फरवरी 2026

जाइका के "हिमट्रेडिशन" उत्पाद बनी लोगों की पहली पसंद

इस अंक में...

- ☞ अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में हिम ट्रेडिशन उत्पादों पर फ़िदा हुए लोग
- ☞ हिमोत्सव में मिली जाइका के उत्पादों को नई पहचान, हुई खूब बिक्री
- ☞ सीपीडी डा. संजय सूद ने लिया परियोजना के कार्यों का फीडबैक
- ☞ प्रोबेशन आईएफएस अफसरों ने लिया जाइका परियोजना का ज्ञान
- ☞ स्वयं सहायता समूहों को पढ़ाया खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पाठ
- ☞ औषधीय खेती की नई पहल, कड़ू के रोपे 16 लाख 20 हजार पौधे
- ☞ आजीविका सुधार की दिशा में 10 हजार 06 लोग बढ़ रहे आगे
- ☞ मेघालय, उडीसा और तमिलनाडू एक्पोजर विजिट से मिला सीखने का मौका

जाइका वानिकी परियोजना दिखा रही आत्मनिर्भरता से आमदनी की राह

जाइका वानिकी परियोजना हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आत्मनिर्भरता से आजीविका सुधार की राह दिखा रही है। यह परियोजना इस दिशा में वर्ष 2018 से बेहतरीन कार्य कर रही है, जो निरंतर जारी है। परियोजना का मुख्य लक्ष्य हिमाचल प्रदेश के चयनित क्षेत्रों में वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं संवर्धन करना, जिससे पर्यावरण एवं सतत सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान मिल सके। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, लाहौल–स्पीति, शिमला और कुल्लू के 9 वृतों, 22 वन मंडलों और 72 वन परिक्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश वन विभाग के सौजन्य से गठित 400 ग्राम वन विकास समितियों और 60 जैव विविधता प्रबंधन उप समितियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सोसायटी अधिनियम–2006 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त सोसाइटी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसका नाम हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना के रूप में नामित किया गया। हिमाचल प्रदेश के 22 वन मंडलों में 912 स्वयं सहायता समूह आजीविका सुधार के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना की कुल लागत 800 करोड़ रुपये है और अवधि 10 वर्ष यानी 2018 से 2028 तक है। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग और जन सहभागिता के अंतर्गत हर साल पौधरोपण किया जाता है। अब तक प्रदेश में लगभग 8 हजार 3 सौ हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण किया जा चुका है।

हिमाचल में हरित आवरण को वर्ष 2030 तक 30 प्रतिशत बढ़ाने के लिए जाइका वानिकी परियोजना का अहम भूमिका निभा रही है। प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना **मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना** और **राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना** के तहत जाइका वानिकी परियोजना प्रदेश की बंजर जमीन पर हरियाली लाने के लिए पौधरोपण अभियान के माध्यम से बेहतरीन कार्य कर रही है। पर्यावरण संरक्षण के साथ पत्तल का कारोबार भी हो रहा है। प्रदेश में आधुनिक तरीके से बन रही पत्तलों की मांग भी काफी बढ़ रही है। टौर के पत्तों से बनी पत्तलें पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हैं, जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यह परियोजना हैंडलूम सेक्टर में बेहतरीन कार्य कर रही है। विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार हो रहे हथकरघा एवं बुनकर उत्पादों को नई पहचान मिल रही है। परियोजना से जुड़े विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बेचने के लिए वन मंडल स्तर पर मार्केटिंग आउटलैट स्थापित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती के लिए जाइका वानिकी परियोजना ने सकारात्मक कदम उठाया है। परियोजना के जड़ी–बूटी प्रकोष्ठ के अंतर्गत किन्नौर, रोहड़ू, चौपाल, आनी और सुकेत में औषधीय पौधों की बेहतरीन खेती की जा रही है। वित्त वर्ष 2024–25 और 2025–26 के दौरान परियोजना ने कड़ू यानी कुटकी के 16 लाख 20 हजार पौधे रोपे गए। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के ग्रामीणों की आजीविका सुधार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही है।

आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

डा. संजय सूद (भा.व.से.)
वन बल प्रमुख एवं मुख्य परियोजना निदेशक

अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में
“हिम ट्रेडिशन” उत्पादों पर फ़िदा हुए लोग

आरपी नेगी

मीडिया स्पेशलिस्ट

11 से 14 नवंबर 2025 तक चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रामपुर लवी मेले में जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के हिम ट्रेडिशन ब्रांड के उत्पाद ख़रीदने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित दिखे। हर वर्ष की भांति इस बार भी रामपुर लवी में जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद यहां बिक्री हो रही है। वन मंडल किन्नौर, रामपुर और आनी के अंतर्गत आने आले 14 स्वयं सहायता समूहों के रसायन मुक्त उत्पादों की खरीद के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। बता दें कि जाइका वानिकी परियोजना के चुल्ली का तेल, राजमाह, कोदे का आटा, घी, किन्नौरी पारंपरिक वस्त्र लोगों की पहली पसंद बन चुकी है।गौरतलब है कि इस परियोजना से जुड़ कर स्वयं सहायता समूह अपनी आजीविका में बेहतरीन सुधार कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदमी में भी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि लवी मेले में इस तरह के उत्पादों की बिक्री हो रही है, लेकिन जाइका वानिकी परियोजना के स्टॉल पर दूसरों के मुकाबले सस्ते दरों पर उपलब्ध हैं। परियोजना निदेशक श्री श्रेष्ठा नंद शर्मा ने बताया कि यह परियोजना रसायन मुक्त उत्पादों के साथ–साथ हथकरघा क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य कर रही है। परियोजना से जुड़े विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हथकरघा और बुनाई उत्पादों को नई पहचान मिल रही है। इन समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को हिम ट्रेडिशन ब्रांड के तहत बाजार में बेचा जा रहा है।

सीएम ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और मंत्री विक्रमादित्य सिंह स्टॉल पर पहुंचे

प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जाइका वानिकी परियोजना के स्टॉल पर पहुंचे। मेले के समापन अवसर पर यानी 14 नवंबर 2025 को उन्होंने प्रदर्शनी एवं बिक्री केंद्रों का मुआयना किया। रिटायर एचपीएफएस श्री सीएम शर्मा ने मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री और लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना भी की।

दिल्ली हाट में मिली जाइका के उत्पादों को नई पहचान

देश की राजधानी दिल्ली हाट परिसर में 15 दिनों तक आयोजित हिमोत्सव में जाइका वानिकी परियोजना ने स्वयं सहायता समूहों के पहाड़ी उत्पाद उतार दिए हैं। यानी 16 से 30 नवंबर तक आयोजित हिमोत्सव के दौरान हिमाचल प्रदेश जाइका वानिकी परियोजना के उत्पादों की खूब बिक्री हुई। हिमोत्सव का आगाज 16 नवंबर 2025 को प्रदेश के मुख्य सचिव श्री संजय गुप्ता ने जाइका वानिकी परियोजना के स्टाल का उदघाटन किया। उन्होंने परियोजना द्वारा लगाए गए सभी स्टाल का मुआयना कर स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की सराहना की। बता दें कि हिमोत्सव हिमाचल की पपरंपरा, कला, खानपान, परिधान समेत अन्य उत्पादों को दिल्लीवासियों के साथ–साथ अन्य राज्यों और देश–विदेशों से सैर करने आए पर्यटकों के समक्ष पेश करने का बेहतर अवसर है। इसके मद्येनजर जाइका वानिकी परियोजना ने 12 स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए 5 स्टाल लगाए हैं। जिसमें हिमाचली परिधान, रसायन मुक्त उत्पाद शामिल हैं। इस बात की जानकारी जाइका वानिकी परियोजना के प्रोग्राम मैनेजर मार्केटिंग एवं रूरल फाइनांसिंग श्री विनोद शर्मा ने दी।

उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली हाट परिसर पर स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी के लिए बेहतर मौका मिल रहा है और नई पहचान भी मिलेगी। इस अवसर पर पीएमयू शिमला से एसएमएस रचना चंदेल, एसएमएस ठियोग डा. अभय महाजन, एसएमएस पालमपुर कृतिका शर्मा, एसएमएस रोहड़ू पारस झगटा, एफटीयू मनाली शुभम, विकेश, एफटीयू ठियोग लाकेंद्र, एफटीयू पालमपुर अनु सूद समेत परियोजना के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सीपीडी डा. संजय सूद ने लिया परियोजना के कार्यों का फीडबैक

वन बल प्रमुख एवं जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक डा. संजय सूद ने 16 दिसंबर 2025 को परियोजना में चल रहे कार्यों का फीडबैक लिया। उन्होंने परियोजना मुख्यालय टुटू में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की। गौरतलब है कि वन बल प्रमुख डा. संजय सूद जाइका वानिकी परियोजना में सीपीडी का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं। इसके मद्देनजर उन्होंने परियोजना के सभी घटकों पर आधारित कार्यों का फीडबैक लिया। आजीविका सुधार, पौधरोपण, जैव विविधता समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। परियोजना निदेशक श्री श्रेष्ठा नंद शर्मा ने डा. संजय सूद को परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 22 वन मंडलों में चल रहे कार्यों के बारे अवगत करवाया। मुख्य परियोजना निदेशक ने पाइप लाइन में चल रहे कार्यों को तय समय पर निपटाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जैव विविधता विशेषज्ञ डा. एसके काप्टा, वित्त अधिकारी श्री गौरी शंकर, प्रोग्राम मैनेजर्स, एसएमएस समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रोबेशन आईएफएस अफसरों ने लिया जाइका परियोजना का ज्ञान

2024 बैच के आईएफएस प्रोबेशन अफसरों ने जाइका वानिकी परियोजना के बारे ज्ञान हासिल किया। अभिषेक परिहार और अजय सिंह मीणा गत 8 जनवरी 2026 को परियोजना प्रबंधन इकाई शिमला पहुंचे। इस अवसर पर परियोजना निदेशक श्री श्रेष्ठा नंद शर्मा ने आईएफएस अफसरों को परियोजना और वन विभाग में चल रहे महत्वपूर्ण कार्यों और गतिविधियों के बारे विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पौधरोपण, आजीविका सुधार और आय सृजन गतिविधियों के बारे अवगत करवाया। जड़ी–बूटी प्रकोष्ठ के निदेशक डा. एसके काप्टा ने जैव विविधता के बारे जानकारी दी।

बता दें कि प्रोबेशन आईएफएस अधिकारी श्री अभिषेक परिहार और श्री अजय सिंह मीणा राजस्थान राज्य से संबंध रखते हैं। परियोजना निदेशक श्री श्रेष्ठा नंद शर्मा ने बताया कि जाइका वानिकी परियोजना का मुख्य लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में सतत् सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए वन क्षेत्रों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। गौरतलब है कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों किन्नौर, शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल–स्पीति और कांगड़ा के 9 वन वृतों, 22 वन मंडलों, 72 वन परिक्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना निदेशक ने अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश जाइका वानिकी परियोजना में 460 ग्राम वन विकास समितियां और 920 स्वयं सहायता समूहों की आजीविका बढ़ाने के लिए प्लान तैयार किए गए हैं।

वनों में हरित आवरण बढ़ाने के लिए परियोजना द्वारा पौधरोपण किया जा रहा है। अब तक 8 हजार 3 सौ हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना और राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत भी प्रदेश में पौधे रोपे जा रहे हैं। इस दौरान प्रोग्राम मैनेजर्स श्री विनोद शर्मा, श्रीमति रीना शर्मा, डा. कौशल्या कपूर, दिशा गौतम और जड़ी–बूटी सैल के मैनेजर मार्केटिंग डा. राजेश चौहान ने अपने–अपने घटकों से संबंधित परियोजना के बारे विस्तृत प्रस्तुति भी दी।

वानिकी परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को पढ़ाया खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पाठ

आरपी नेगी
मीडिया स्पेशलिस्ट

जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पाठ पढ़ाया। बीते 18 दिसंबर 2025 को मंडी, किन्नौर के निगुलसरी में 8 जनवरी 2026, रामपुर में 9 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को रोहड़ू के स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों को उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान फॉसटैक यानी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट की पाठशाला चली। आईआईईएसटी फेडरेशन दिल्ली के प्रतिनिधियों ने एफएसएसएआई द्वारा जारी आदेश के तहत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिए।

फेडरेशन के निदेशक अनिल शर्मा और एरिया को–ऑर्डिनेटर मोहर सिंह ठाकुर ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को हरेक पहलुओं की ट्रेनिंग दी। प्रशिक्षण शिविर के दौरान किन्नौर, मंडी और रोहड़ू के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने स्वयं सहायता समूहों खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के बारे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद तैयार करने होंगे। ताकी उत्पादों की गुणवत्ता बरकरार रह सके। बता दें कि जाइका वानिकी परियोजना समय–समय पर स्वयं सहायता समूहों को उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग देती है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न वन मंडलों में आजीविका सुधार के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूह आचार, चटनी, सेपू–बड़ी, छरमा का जूस समेत अन्य उत्पाद तैयार कर रहे हैं। प्रोग्राम मैनेजर विनोद शर्मा ने बताया कि परियोजना से जुड़े सभी स्वयं सहायता समूहों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश के शेष अन्य वन मंडलों में भी स्वयं सहायता समूहों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि यह शेडयूल पहले से ही प्रस्तावित है, लेकिन राज्य में 23 जनवरी से खराब मौसम के चलते स्थगित किया गया।

परियोजना निदेशक ने माननीयों को डायरी भेंट कर दी नव वर्ष की बधाई

परियोजना निदेशक श्री श्रेष्ठा नंद शर्मा ने प्रदेश सरकार के माननीयों को वर्ष 2026 की डायरी भेंट पर नव वर्ष की बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया श्री नरेश चौहान और मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन श्री बुद्धि सिंह ठाकुर को परियोजना की 2026 की डायरी भेंट की। श्री नरेश चौहान और श्री बुद्धि सिंह ठाकुर ने परियोजना में चल रहे कार्यों की सराहना की।

औषधीय खेती की नई पहल, कडू के रोपे 16 लाख 20 हजार पौधे

डा. राजेश चौहान

मैनेजर मार्केटिंग (जड़ी-बूटी प्रकोष्ठ)

हिमाचल प्रदेश में विलुप्त हो रहे औषधीय पौधों को जिंदा करने और इनकी खेती के लिए जाइका वानिकी परियोजना ने नई पहल शुरू की है। इसमें मुख्य रूप से कडू की खेती के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत विभिन्न वन मंडलों में बनी ग्राम वन विकास समितियों और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से अब तक यानी वित्त वर्ष 2025—26 तक कडू यानी कुटकी के 16 लाख 20 हजार पौधे रोपे गए। जो अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। गौरतलब है कि परियोजना ने वन मंडल किन्नौर के तरांडा और निगानी में 1 लाख, वन मंडल आनी के बागा सराहन और सरगा में 2 लाख 20 हजार और शरशा में 3 लाख, वन मंडल कुल्लू के माटी कोचर में 1 लाख 75 हजार, वन मंडल रोहड़ू के डोडरा—क्वार में 4 लाख, खशधार में 3 लाख, वन मंडल चौपाल के बम्टा में 1 लाख 70 हजार, सराहन में 3 लाख 60 हजार, वन मंडल बंजार के सैंज में कडू के 90 हजार पौधे रोपे गए। बताया गया कि इस औषधीय पौधों की खेती पूरी तरह से रसायन मुक्त होती है। इससे जल स्रोतों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।

2 से 5 हजार रूपये प्रति किलो मिल रही कीमत

वर्तमान में कडु को स्थानीय बाजार में दो से पांच हजार रूपये प्रति किलोग्राम से हिसाब से कीमत मिल रही है। इसके अलावा औषधीय गणों से भरपूर चिरायता की खेती भी परियोजना के अंतर्गत की जा रही है। वर्तमान में चिरायता तीन से पांच सौ रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। बता दें कि जाइका वानिकी परियोजना प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर, वन मंडल आनी, रोहड़ू, चौपाल और कुल्लू के विभिन्न क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है।

कडू की जड़ों से तैयार हो रहा दवा

पिक्रोरिज़ा कुरोआ (कुटकी) यानी कडू एक ऐसा औषधीय पौधा है जो विलुप्त होने की कगार पर है। इस पौधे का उपयोग पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों दोनों में किया जाता है, जहां इसकी जड़ों से दवा तैयार की जाती है। स्थानीय विक्रेताओं द्वारा अवैज्ञानिक दोहन के कारण यह पौधा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। पश्चिमी हिमालय में इसके सीमित वितरण क्षेत्र, छोटी आबादी और उच्च मूल्य के कारण इसे संरक्षण और खेती के लिए पहचाने गए 37 शीर्ष प्राथमिकता वाले पौधों में शामिल किया गया है।

कडू के औषधीय उपयोग

स्थानीय लोगों द्वारा पेट पर्द और तेज बुखार जैसी बीमारियों के इलाज के लिए कडू को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अलावा बिच्छू के डंक के इलाज, ब्लड प्रेशर, आंतों के दर्द, आंखों की बीमारी, पित्त रोग और गले की खराश के उपचार में उपयोगी है। बताया जा रहा है कि नेपाल और तिब्बती चिकित्सा विशेषज्ञ खांसी, जुकाम और बुखार के लिए राइजोम का उपयोग करते हैं।

"प्रदेश में विलुप्त हो रहे औषधीय पौधे कडू की खेती के लिए जाइका वानिकी परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वित्त वर्ष 2024 से लेकर 2026 तक 6 वन मंडलों में कडू के 16 लाख 20 हजार पौधे रोपे गए, आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे"

— डा. एसके काप्टा, निदेशक जड़ी—बूटी प्रकोष्ठ

आजीविका सुधार की दिशा में 10 हजार 06 लोग बढ़ रहे आगे

रचना चंदेल

विषय वस्तु विशेषज्ञ, पीएमयू शिमला

जाइका वानिकी परियोजना पिछले सात वर्षों यानी वर्ष 2018 से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। राज्य के 22 वन मंडलों में कार्यांवित इस परियोजना के अंतर्गत 920 स्वयं सहायता समूह, 400 ग्राम वन विकास समितियों और 60 जैव विविधता उप समितियों के 10 हजार 6 लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं।

जो आत्मनिर्भरता से आजीविका सुधार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यह हर्ष की बात है कि इस परियोजना में महिलाओं की भागिदारी पुरूषों की तुलना में कहीं अधिक हैं। यानी 94 प्रतिशत महिलाएं इस परियोजना से जुड़कर अपनी आर्थिकी में सुधार कर रही हैं। बता दें कि 920 स्वयं सहायता समूहों में 10 हजार 6 सदस्यों में से 9282 महिलाएं और 724 सदस्य पुरूष हैं।

इसके अलावा 22 वन मंडलों और 72 वन परिक्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी परियोजना में रोजगार के अवसर मिल चुके हैं, जो अपनी आजीविका कमा रहे हैं। कुल मिलाकर जाइका वानिकी परियोजना हिमाचल में वन तंत्र प्रबंधन, सामुदायिक विकास एवं आजीविका सुधार के लिए कार्य कर रही है।

परियोजना का मुख्य लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में सतत् सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए वन क्षेत्रों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। गौरतलब है कि जाइका वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना के तहत राज्य में लोगों के माध्यम से परियोजना का कार्यान्वयन हो रहा है।

मशरूम की खेती, पत्तल का कारोबार, हथकरघा एवं बुनकर, सिलाई–कटाई और मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण करने सहित कई गतिविधियां चल रही हैं।

मेघालय, उडीसा और तमिलनाडू एक्सपोज़र विजिट से मिला सीखने का मौका

मेघालय

तमिलनाडू

उड़ीसा

हिमाचल प्रदेश जाइका वानिकी परियोजना की 3 टीम मेघालय, उडीसा और तमिलनाडू राज्य के एक्सपोजर विजिट पर रही। पहली टीम 24 से 28 नवंबर 2025 तक मेघालय गई। उसके बाद दो टीम 19 से 25 जनवरी 2026 तक उडीसा और तमिलनाडू दौरे पर रही। इस दौरान टीम के सदस्यों को संबंधित राज्यों में जाइका वानिकी परियोजना के तहत हुए बेहतरीन कार्य देखने का मौका मिला। बता दें कि मेघालय, तमिलनाडू और उडीसा राज्य में जाइका परियोजना ने वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विकास कार्यों को अंजाम दिया, जिसे देख हिमाचल के प्रतिनिधियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला।

मीडिया में जाइका वानिकी परियोजना...

Hindustan Times

HP: Japan-backed forestry project aiding revival of endangered medicinal plants

Shailee Dogra
shailee.dogra@htlive.com

Up to financial year 2025-26, around 1.62 million Kadu saplings have been planted across various forest divisions in the state. HT

SHIMLA : With a bid to revive endangered medicinal plants and promote their scientific cultivation, the Japan International Cooperation Agency (JICA) forestry project in Himachal Pradesh, said an official spokesperson.

Special focus has been given on "Picrorhiza kurroa", locally known as Kadu or Kutki, a medicinal plant on verge of extinction owing to unscientific extraction by local traders. The plant's roots are used for medicinal preparation.

Under the initiative, rural communities are being encouraged to take up medicinal plant farming with support from village forest development committees and self-help groups formed under the project. The spokesperson informed that up to the financial year 2025-26, around 1.62 million Kadu saplings have been planted across various forest divisions in the state, marking a significant conservation and livelihood milestone.

Owing to its limited distribution in the western Himalayas, small populations, and high market value, Kutki has been included among the 37 top-priority plant species identified for conservation and cultivation. Its farming can provide an alternative source of income as well as generate self-employment opportunities. At present, Kadu is fetching a price of ₹2,000 to ₹5,000 per kilogram in local markets.

Locals highly value Kadu as it is used for treating stomach ailments and high fever. It is also used in the treatment of scorpion stings, blood pressure, intestinal pain, eye disorders, bile-related diseases, and sore throat. It is reported that medical practitioners in Nepal and Tibetan medicine use its rhizome to treat cough, cold and fever.

An official associated with the project said that cultivation of this medicinal plant is completely chemical-free and does not harm water sources. Around 1,00,000 saplings in Taranda and Nigani areas of Kinnaur Forest Division, 2,20,000 in Baga Sarahan and Sarga, and 3,00,000 in Sharsha under Ani Forest Division have been planted along with 1,75,000 saplings in Mati Kochar of Kullu Forest Division; 4,00,000 in Dodra-Kwar; 3,00,000 in Khashdhar under Rohru forest division; 1,70,000 in Bamta; 3,60,000 in Sarahan under Chopal Forest Division and 90,000 saplings in Sainj area of Banjar Forest Division.

Cultivation of Chirayata another medicinal plant rich in therapeutic properties, is also being promoted under the project. Currently, Chirayata is selling at ₹300 to ₹500 per kilogram.

The JICA forestry project is carrying out work to promote medicinal plant cultivation in tribal district Kinnaur and forest divisions of Ani, Rohru, Chopal and Kullu. "The JICA forestry project is playing an important role in promoting the cultivation of the endangered medicinal plant Kadu in the state. From the financial year 2024 to 2026, 1.62 million Kadu saplings have been planted across six forest divisions. Positive results will be seen in the coming years," Dr SK Kapta, director, Jadi-Buti Cell JICA forestry project, said. "The demand for natural products is increasing. This is a rare plant and it was earlier found at high altitudes where the tree line used to end. So through JICA we have been provided nurseries and now we have started plantation. This promises high return considering the demand which not just help in revival of the species but also financial independence of the cultivators," shared Ajay Negi of village forest development committees, Nigani.

प्रोबेशन आईएफएस अफसरों ने लिया जाइका परियोजना का ज्ञान,

परियोजना निदेशक श्रेष्ठा नंद शर्मा ने दी विस्तृत जानकारी,

SUMMER न्यूज़

निदेशक जड़ी-बूटी सैल प्रकोष्ठ डा. एसके काप्टा ने किया जैव विविधता के बारे में अवगत

निगुलसरी में फूड सेफ्टी पर दी ट्रेनिंग

स्वयं सहायता समूहों को पढ़ाया खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पाठ

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-रिकांगपिओ

जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को निगुलसरी में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पाठ पढ़ाया। गुरुवार को वन मंडल किन्नौर के निगुलसरी में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 12 स्वयं सहायता समूहों के 58 प्रतिनिधियों को उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे जानकारी दी गई। इस दौरान फॉसटैक यानी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट की पाठशाला आयोजित की। आईआईईएसटी फेडरेशन दिल्ली के प्रतिनिधियों ने एफएसएसएआई द्वारा जारी आदेश के तहत प्रशिक्षण दिए। फेडरेशन के निदेशक अनिल शर्मा और एरिया को-ऑर्डिनेटर मोहर सिंह ठाकुर ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को हरेक पहलुओं की ट्रेनिंग दी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी किन्नौर अदिति नेगी ने स्वयं सहायता समूहों खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के बारे जानकारी दी। एफएसएसएआई के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद तैयार करने होंगे, ताकी उत्पादों की गुणवत्ता बरकरार रह सके। शिविर में रिटायर एचपीएफएस सीएम शर्मा, वन परिक्षेत्राधिकारी परमानंद, एसएमएस राधिका नेगी, एफटीयू कोऑर्डिनेटर प्रियंका नेगी, सुरेखा नेगी, पुनम नेगी और सविता नेगी समेत परियोजना के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

रिकांगपिओ प्रशिक्षण के दौरान स्वयं सहायता समूह के सदस्य

मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने किया स्टाल का उदघाटन

दिल्ली हाट में जाइका ने उतारे स्वयं सहायता समूहों के पहाड़ी उत्पाद

आज समाज नेटवर्क

शिमला। देश की राजधानी दिल्ली हाट परिसर में 15 दिनों तक चलते वाले हिमोत्सव में जाइका वानिकी परियोजना ने स्वयं सहायता समूहों के पहाड़ी उत्पाद उतार दिए हैं।

रविवार यानी 16 नवंबर को हिमोत्सव का आगाज हुआ तो प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने जाइका वानिकी परियोजना के स्टाल का उदघाटन किया।

उन्होंने परियोजना द्वारा लगाए गए सभी स्टाल का मुआयना कर स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की सराहना की। बता दें कि हिमोत्सव हिमाचल की परंपरा, कला, खानपान, परिधान समेत अन्य उत्पादों को दिल्लीवासियों के साथ-साथ अन्य राज्यों और देश-विदेशों से सैर करने आए पर्यटकों के समक्ष पेश करने का बेहतर अवसर है। इसके मद्देनजर जाइका वानिकी परियोजना ने 12 स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए 5 स्टाल लगाए हैं।

जिसमें हिमाचली परिधान, रसायन मुक्त उत्पाद शामिल हैं। इस बात की जानकारी जाइका वानिकी परियोजना के प्रोग्राम मैनेजर मार्केटिंग एवं रूरल फाइनांसिंग विनोद शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली हाट परिसर पर स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी के लिए बेहतर मौका मिल रहा है और नई पहचान भी मिलेगी। इस अवसर पर पीएमयू शिमला से एसएमएस रचना चंदेल, एसएमएस ठियोग डा. अभय महाजन, एसएमएस पालमपुर कृतिका शर्मा, एसएमएस रोहड़ू पारस झगटा, एफटीयू मनाली शुभम, विकेश, एफटीयू ठियोग लाकेंद्र, एफटीयू पालमपुर अनु सूद समेत परियोजना के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मंडी में चली स्वयं सहायता समूहों की फॉसटैक की पाठशाला

- जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े एसएचजी के सदस्यों को दी ट्रेनिंग
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बेहतरीन उत्पाद तैयार करने पर दिया बल

एलोवेरा खेती से सोना उगलने लगे बंजर खेत

सुकेत और कांगू रेंज के तीन स्थानों में रोपे गए हैं 25-25 हजार एलोवेरा के पौधे

संवाद न्यूज एजेंसी

सुंदरनगर (मंडी)। कभी लावारिस पशुओं और सिंचाई सुविधाओं के अभाव में बंजर हो चुकी भूमि आज हरियाली से लहलहा रही है। ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का मजबूत आधार बन गई है। हिमाचल प्रदेश जाइका वानिकी परियोजना के सहयोग से सुंदरनगर क्षेत्र के सुकेत वनमंडल में एलोवेरा खेती को नई पहचान मिली है।

ग्रामीणों की मेहनत का परिणाम है कि आज यह फसल बाजार तक पहुंच चुकी है। सुकेत और कांगू रेंज के तीन स्थानों पर 25-25 हजार एलोवेरा पौधे रोपे गए। ग्राम पंचायत बायला के गांव रोपड़ी तथा ग्राम पंचायत धवाल का ग्राम अपर बाड़ी को परियोजना के पहले चरण में शामिल किया गया था।

2022 में परियोजना की ओर से लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह को 25 हजार एलोवेरा पौधे निशुल्क उपलब्ध करवाए। दूसरे चरण में ग्राम पंचायत अरठी का गांव थला शामिल किया गया।

सितंबर 2022 तथा 2023 में लक्ष्मी शिव गौरी, सरस्वती स्वयं सहायता समूहों और हमीरपुर की एक निजी कंपनी के बीच एलोवेरा उत्पादों की खरीद के लिए समझौता ज्ञापन किया गया। सुकेत वन मंडल के एसएमएस डॉ. विजय कुमार के अनुसार, यह परियोजना प्रदेश के 22 वनमंडलों में लागू की जा रही है और इसका उद्देश्य वन आधारित आजीविका को सशक्त बनाना है। वहीं, वनमंडल अधिकारी राकेश कटोच ने बताया कि जाइका परियोजना के सहयोग से बंजर भूमि पर एलोवेरा खेती ने ग्रामीणों के लिए आय का नया रास्ता खोला है।

हमीरपुर की निजी कंपनी के बीच एलोवेरा उत्पादों की खरीद के लिए हुआ है समझौता ज्ञापन

दो साल बाद मिला मेहनत का फल

एलोवेरा फसल लगभग दो वर्षों में तैयार होती है। इस अवधि के बाद तीनों स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 32,500 रुपये के एलोवेरा पौधे तथा 35,253 रुपये की एलोवेरा पत्तियां बेचकर आय अर्जित की। पौधे उपलब्ध कराने वाली कंपनी ही दो वर्षों के बाद एलोवेरा की पत्तियां और बेबी प्लांट्स खरीद लेती है। एक एलोवेरा पौधा लगभग 10 वर्षों तक उत्पादन देता है।

सुंदरनगर में विकसित किए गए एलोवेरा के खेत। स्रोत : विभाग

खेती जंगली जानवरों और पक्षियों की वजह से उजड़ गई थी। जाइका प्रोजेक्ट ने एलोवेरा खेती करवानी शुरू की है। अब किसी भी तरह की उजाड़ नहीं होती है। हमें इस बंजर भूमि से कमाई का एक नया जरिया मिला है।
-देश राज लाभार्थी, निवासी बायला

इस खेती से बेशक अभी इतनी कमाई तो नहीं हो रही है लेकिन जाइका ने उन्हें एक विकल्प जरूर दे दिया है। मैंने इस बार सात क्विंटल एलोवेरा से 5600 रुपये की पहली कमाई एक बीघा से की है जहां पर पहले कुछ नहीं होता था।
-सुरेश कुमार किसान हवानी

स्वयं सहायता समूह ने चीड़ की सुइयों से बनाए अनोखे हस्तशिल्प

6.85 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया

चीड़ की सुइयों से हस्तशिल्प बनाने की प्रक्रिया

चीड़ की पत्तियों से उत्पाद, जंगलों में आग से भी बचाव

महिलाओं को किया प्रेरित

जाइका वानिकी परियोजना ने खोले रोजगार व स्वरोजगार के द्वार, आजीविका सुधार की दिशा में काम कर रहे 10 हजार लोग

आजीविका सुधार के क्षेत्र में 24 मॉडल

जनसहभागिता व विभागीय स्तर पर पौधारोपण

920 स्वयं सहायता समूह गठित

https://www.facebook.com/mandi.khabarnama/

दैनिक संध्या अखबार **मंडी खबरनामा** ...सही खबर आप तक

बटन और ढींगरी मशरूम की खेती से 20,70827 रुपये की रिकार्ड बिक्री

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें

मुख्य परियोजना निदेशक, जाइका वानिकी परियोजना

नजदीक मिल्कफैड निगम, टुटू शिमला-11 हिमाचल प्रदेश

दूरभाष: 0177.28372172837317/2838217

email: cpdjica2018hpfd@gmail.com https://jicahpforestryproject.com

अतिरिक्त परियोजना निदेशक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई

जाइका वानिकी परियोजना, कुल्लू। दूरभाष: 01902-226636, ई0 मेल: pdjicakullu@gmail.com